

निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार ने बिना अनुमति काट दिए बड़े-बड़े पेड़

छिंदवाड़ा, देशबन्धु। पर्यावरण और वन संरक्षण की मुहिम से विपरीत निर्माण कार्य के लिए प्रशासन को ताक पर रखकर बिना पुराने बड़े पेड़ काटे जाने को लेकर ठेकेदार को मनमानी सामने आ गई है। तामिया से छिंदवाड़ा मुख्यमंत्री में वन विभाग का यांत्रिक थे के सामने पुराने माध्यमिक शाला भवन को ढहा कर नया नवीन बालक छात्रावास भवन का निर्माण हो रहा है।

इस निर्माण के लिए ठेकेदार ने बिना अनुमति बड़े-बड़े पेड़ ढहा दिए हैं। स्त्रों की मानें तो ठेकेदार ने कलेक्टर से अनुमति की अपवाह फैलाकर ये कानूनामा किया है। निर्माण स्थल में निर्माण एजेंसी का कोई सूचना बोर्ड नहीं है। तीन दिन पहले भवन के आसपास के पुराने बड़े नीलगिरी के पेड़ काट कर गिराए गए हैं। पहले भी ठेकेदार ने जेसीबी से पांच से ज्यादा पेड़ उत्थाइ कर नदी के पास सरका दिए थे।

स्थानीय पंचायत, वन विभाग और राजस्व के पास अनुमति की कोई सूचना नहीं है। इस निर्माण कार्य में चूनक इंप्रस्ट्रक्चर की पुरातला की जानकारी सामने आई है, निर्माण कार्य को बोर्ड नहीं है। एक दिन पहले तहसीलदार श्री बारले



भी मौके का मायावना करने जा चुके हैं। इस संबंध में रेजर हिमांशु निश्चिकर्मा ने बताया कि पेड़ काटने की अनुमति लेकर ठेकेदार या पर्म का फेन आया था, प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली थी, लेकिन

अनुमति नहीं ली। एक अप्रैल से नियम बदल गए हैं। पंचायत, राजस्व से अनुमति के लिए निर्धारित प्रक्रिया है। तामिया में नवीन बालक छात्रावास सहित अन्य निर्माण कार्यों में अधिकारियों

के खुले संरक्षण और कंसल्टेंसी के सहयोग से मनमाने रात तक से को काटने के साथ अवैध रेत का इस्तेमाल हो रहा है। निर्माण वक्षाली अनुमति लेने की लागत एवं उसकी समय सीमा निर्माण एजेंसी विभाग की जानकारी नहीं मिल पा रही है।

नहीं हुई, वहीं निर्माण के लिए पुराने पेड़ों की बाल चढ़ा दी गई है।

तामिया में 9 से अधिक पेड़ों को बिना अनुमति काटे जाने का मामला सामने आने के बाद अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। पुराने बालक माध्यमिक स्कूल परिसर में नवा बड़ा भवन निर्माण हो रहा है। इसमें भी निर्माण कार्य की जानकारी देने वाला बोर्ड नहीं लगाया गया है। जिससे निर्माण कार्य की लागत एवं उसकी समय सीमा निर्माण एजेंसी विभाग की जानकारी नहीं मिल पा रही है।

यहां पर रेत का अवैध भंडारण भी ठेकेदार द्वारा अपने निर्माण के स्थल पर किया जा रहा है, लेकिन ना तो राजस्व खनिज विभाग अब इन पर कोई कार्रवाई करने को तेवर है, लेकिन उससे भी गंभीर मामला देखने मिल रहा है कि निर्माण स्थल पर लेआउट कर दिया गया है, लेकिन इस लेआउट के बीच में हरे भरे सात नीलगिरी के पेड़ स्थापित थे अनुमति लेने की बजाय ठेकेदार इन्हें मशीन से उत्थाइ कर फेंक दिया। हरे वृक्ष नियमानुसार विभाग को कटवाना था। इसके अलावा पर्यावरण के साथ-साथ वक्षाली नियम का भी खुला उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि इन्हें ठेका मिला है तो

निश्चित ही इन पेड़ों को विधिवत काटने की अनुमति भी संबंधित विभाग माध्यम से मिलेगी।

एक अप्रैल से बदल गए नियम पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश के संचालन सह-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय द्वारा 25 अप्रैल 2025 को समस्त म.प्र. के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला एवं जनपद पंचायत को ग्रामीणों की निजी भूमि पर वक्ष काटाई की अनुमति आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संपादित करने वाले बोर्ड पर भेजा है। निजी भूमि पर वक्ष काटाई की अनुमति आनलाइन प्रक्रिया की जाएगी। 1 अप्रैल से किसी भी प्रकार से सरपर द्वारा जारी किया गया आफ्लाइन अनुमति पर मात्र नहीं होगा।

इनका कहना है यहां पर रेत का अवैध भंडारण भी ठेकेदार द्वारा अपने निर्माण के स्थल पर किया जा रहा है, लेकिन ना तो राजस्व खनिज विभाग अब इन पर कोई कार्रवाई करने को तेवर है, लेकिन उससे भी गंभीर मामला देखने मिल रहा है कि निर्माण स्थल पर लेआउट कर दिया गया है, लेकिन इस लेआउट के बीच में हरे भरे सात नीलगिरी के पेड़ स्थापित थे अनुमति लेने की बजाय ठेकेदार इन्हें मशीन से उत्थाइ कर फेंक दिया। हरे वृक्ष नियमानुसार विभाग को कटवाना था। इसके अलावा पर्यावरण के साथ-साथ वक्षाली नियम का भी खुला उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि इन्हें ठेका मिला है तो

हिमांशु विश्वकर्मा, रेंजर

सार-समाचार

किसानों को मुआवजा देकर नहर मरम्मत की जाये : किसान कांग्रेस

छिंदवाड़ा, देशबन्धु। सांवरी क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के उपरान्त जलालय की पालाखेड़ नहर के दूरने से क्षेत्र में अनेकों की फसल बहने और अन्य परिसंचयों को भी क्षति पहुंची है। जिला किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चैधरी पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि किसानों की मिका एथन और उद्यानीकी फसलों साथित मलचिंग और डिप को नहर टूटने से नुकसानी की जानकारी प्राप्त हुई है, उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग द्वारा नहर की मरम्मत और सफाई नहीं किये जाने एवं नहर के दूरने से पानी के खेतों में बहने से किसानों को नुकसान झेलना पड़ा। प्रभावित किसानों की फसलों का नुकसानी का सर्व कावकार उन्हें मुआवजा देकर एवं लातेकर एवं लातेकर उत्थाइ करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये जिला किसान कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्टर, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग को ज्ञापन प्रेषित किया है।

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग छिंदवाड़ा द्वारा की जा रही जल लोटों की जियोटेंगिं

छिंदवाड़ा, देशबन्धु। 30 मार्च से 30 जून 2025 तक आयोजित हो रहे जल गंगा संवर्धन अधियन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग जिला छिंदवाड़ा द्वारा कार्य पालन यंत्री सुधार्यु जैन के निर्देशन में नल-जल योजनाओं के स्वोतों की जियोटेंगिं, नल-जल योजनाओं के अंतर्गत पाईप लाइन लोकेज, टपकते नल सुधारना, टूटे नल बदलना, पानी के अपव्य की समस्याओं के लिये आवश्यक कदम, जल स्वोतों की साफ सफाई आदि कार्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। अधियन के अंतर्गत अब तक 1411 जल स्वोतों की जियोटेंगिं, 25 रिचार्ज शॉप प्रस्ताव, 297 पाईप लाइन लिंके, 562 नलों के लीकेज, 500 टूटे नल बदले एवं प्रचार-प्रसार की 176 गतिविधियां आदि कार्य किये गये।

ग्रीष्मकालीन पसल मूँग एवं उड़द के पंजीयन की अतिम तिथि 05 जुलाई

छिंदवाड़ा, देशबन्धु। शासन के निर्देशानुसार भारत सरकार की प्राईस सोपोर्ट स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में ई-उपार्जन पोर्टल पर 19 जून 2025 से 05 जुलाई 2025 तक ग्रीष्मकालीन पसल मूँग एवं उड़द का पंजीयन 05 जुलाई 2025 तक निर्धारित किये गये पंजीयन केन्द्रों पर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज दिनांक तक 1564 किसानों द्वारा 4038 हेक्टेयर रक्केब के पंजीयन कराया गया है।

आपातकाल लगाना सविधान की हत्या थी, युवाओं से हुई चर्चा में बताया मुख्यमंत्री ने

छिंदवाड़ा, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आपातकाल लगाने करना तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा सविधान की हत्या थी। आपातकाल लगाने के संबंध में न केंद्रीय कैविनेट ने स्वीकृती दी थी न ही राज्यों की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव दिया गया था। जिम्मेदार लोगों ने ही सविधान का पालन नहीं किया। अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं से आपातकाल लगाने की विशेषता और विचार करने के संबंध में न केंद्रीय कैविनेट ने स्वीकृती दी थी और राज्यों की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव दिया गया था। जिम्मेदार लोगों ने ही सविधान का पालन नहीं किया। अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि आपातकाल लगाने के प्रसंग पर प्रश्न पूछे और उन्हें मूजूदा दौर की विशेषताओं पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुशाभाऊ थाकरे इंटर स्टेट बस टर्मिनल स्थित नगर निगम भोपाल के सभाकाश में शुक्रवार को आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करते हुए उत्कृष्ट बात कही।

युवा संसद को वरिष्ठ संसद वी.डी. शमा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को इमरजेंसी का प्रसंग बताया जाना आवश्यक है। अनेक युवाओं ने आपातकाल लगाने को लोकतंत्र विवरी बताया।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सविधान हत्या दिवस 25 जून 2025 से निरंतर एक वर्ष तक विभिन्न गतिविधियों के संचालन के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में मध्यप्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के साथ ही विभिन्न स्पर्धाओं और वैचारिक गोष्ठियों के कार्यक्रम, विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगातार किए जा रहे हैं।

रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्कलेव का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित

